



- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी दरों में किए गए सुधारों की सराहना करते हुए कहा—ये सुधार सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा।
- मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि लाइसेंस वितरित किए गए।
- प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत विद्युत विभाग की ओर से आज से जागरूकता शिविर का आयोजन।
- दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जीएसटी दरों में किए गए अगली पीढ़ी के सुधारों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती का फैसला किया है जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रिया सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। उन्होंने कहा कि ये सुधार सभी के लिए खासकर छोटे व्यापारियों, व्यवसायों और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे।

इस बीच, दवा उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर में किए गए सुधारों से जीवन रक्षक दवाओं की सामर्थ्य बढ़ेगी और साथ ही जन स्वास्थ्य की भी बेहतरी होगी। संशोधन के अनुसार, जीवन रक्षक दवाओं, स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों और कुछ चिकित्सा उपकरणों पर कर की दर 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य कर दी गई है।



सरकार ने लोगों को प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के फर्जी पोर्टल के लिए आगाह किया है। कुछ वेबसाइट सरकार के उपक्रम होने का झूठा दावा कर रही हैं। सभी नागरिकों,

नियोक्ताओं और हितधारकों को धोखाधड़ी वाली वेबसाइट और भर्ती के झूठे दावों से सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे ऐसे पोर्टल के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और न ही कोई भुगतान करें।



प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत, कल मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत में भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि लाइसेंस वितरित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करना है। कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रधान, फरारगंज तहसीलदार, बीडीओ, पंचायती राज संस्था के सदस्य और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिला उपायुक्त ने सीडी ब्लॉक फरारगंज के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि लाइसेंस सौंपे। प्रत्येक लाभार्थी को योजना के तहत मकान बनाने के लिए 50 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई। इसके अलावा प्रत्येक लाभार्थी को तीन किशतों में एक लाख बीस हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत घरेलू आवास के निर्माण के लिए 12 हजार रुपये और मनरेगा योजना के तहत 90 मानव दिवस का रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।



दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने हाल ही में ओग्राब्राज में हुए भूस्खलन से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। भूस्खलन के कारण गाँव की लगभग 40 मीटर सड़क धंस गई। स्थिति का जायजा लेते हुए, उपायुक्त ने क्षेत्र में बार-बार हो रही भूस्खलन की घटनाओं के कारण लोगों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। उन्होंने सहायक अभियंता को क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़क की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए एक अनुमानित लागत तैयार करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने भूस्खलन को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार और जल निकासी व्यवस्था का निर्माण करने का निर्देश दिया।



प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर आरटीएस संयंत्रों की स्थापना और लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग आज से राजस्व अधिकारियों के साथ द्वीपसमूह के विभिन्न स्थानों पर 15-दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित कर रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से योजना के लाभों के जानकारी देना, मौके पर पंजीकरण सुविधा प्रदान करना है। इस सिलसिले में आज बिडनाबाद और सीपीघाट ग्राम पंचायत में सुबह दस बजे शिविर लगेगा। इसी प्रकार के शिविर द्वीपों के तीनों जिलों में आयोजित किए जाएंगे। विभाग ने आम जनता से शिविरों का लाभ उठाने का अनुरोध किया है।



टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आंकलन करने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय में कल एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला अस्पताल, विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यक्रम अधिकारियों सहित राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। उपायुक्त ने चल रहे अभियान के तहत गतिविधियों के कार्यान्वयन में चिकित्सा अधिकारियों के निरंतर प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्क्रीनिंग लक्ष्य का 72.43 प्रतिशत पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। उन्होंने शीघ्र उपचार शुरू करने, निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करने और मरीजों द्वारा पूरा कोर्स पूरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उपायुक्त ने गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और पंचायती राज संस्थाओं से निक्षय पोषण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से पोषण संबंधी सहायता को बढ़ावा देने में भाग लेने का आह्वान किया। बैठक में गाँव, ब्लॉक और जिले सहित हर स्तर पर निरंतर निगरानी और आवधिक समीक्षा की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।



प्रशासन की ओर से अंडमान निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्य पालन (संशोधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना मत्स्य विभाग की वेबसाइट के अलावा प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।



अंडमान निकोबार प्रशासन का आधिकारिक डोमेन **Andaman.gov.in** बदलकर **andamannicobar.gov.in** कर दिया गया है। इस कारण सभी आवेदनों के नए डोमेन में

स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। इस कार्य के कल तक पूरा होने की संभावना है। इस दौरान ऑनलाइन प्रक्रिया बंद रहेगी। स्थानांतरण प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आवेदन नए डोमेन पर उपलब्ध रहेगी।



द्वीपसमूह के एकाध स्थानों पर आज और कल तेज़ हवा के साथ वर्षा हो सकती है। 6 और 7 सितंबर को निकोबार द्वीपसमूह में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 35 से 45 किमी प्रति घंटे की गति से चलेगी, जो बढ़कर 55 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते समुद्र अलगांत रहेगा।



श्री विजयपुरम नगरपालिका परिशद की ओर से मरीना पार्क में रेस्टोरेंट के आवंटन हेतु ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की गई है। इस संबंध में नियम और शर्तों वाले निविदा दस्तावेज़ eprocure.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। निविदा 18 सितम्बर भाम 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। निविदा उसी दिन भाम 4 बजे निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नगरपालिका परिशद के राजस्व अधिकारी के कक्ष में खोली जाएगी।

